

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 —उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 105]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 15, 1971/ज्येष्ठ 25, 1893

No. 105

NEW DELHI, TUESDAY JUNE 15, 1971/JYAISTHA 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June 1971

G.S.R. 944.—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, V. V. Giri, President of India, have received a report from the Governor of the State of Punjab and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(611)

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

articles 167 and 169;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article; articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

article 189, 193, 194, 195 and 196;

article 198;

Clauses (3) and (4) of article 199;

articles 200 and 201;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively;

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361, and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule, or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of

clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Punjab General Clauses Act, 1898 (Punjab Act 1 of 1898), as in force in the State of Punjab, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

NEW DELHI:

The 15th June, 1971.

V. Y. GIRI,

President.

NEW DELHI:

The 15th June, 1971.

GOVIND NARAIN,

Secretary.

गृह मंत्रालय

अधिमूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 1971

जी० एस० आर० 944.—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है —

यतः मुझे व० वे० गिरि, भारत के राष्ट्रपति को पंजाब राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा उस रिपोर्ट पर और मुझे प्राप्त अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा सावधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता कि मैं —

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूं ;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी; और

(ग) निम्नलिखित अनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिये मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् —

(i) इस उद्घोषणा के उपयुक्त खंड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिये गये कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिये भारत के राष्ट्रपति

के रूप में उस सीमा तक जिस तक में ठीक समझू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के एतद्वारा निम्नलिखित किया जाता है अर्थात् :-

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निवेश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का सम्बंध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किये गये प्रति-वेदनों को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है—अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का सम्बंध राज्य सरकार के कार्यों का मंतियों के बीच आबंधन से है

अनुच्छेद 176 और 169 ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क) अनुच्छेद, 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) अनुच्छेद 179 का खंड (ख) (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181)

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का सम्बंध सभा के उपध्यक्ष के सम्मन्धों और मतों से है, अनुच्छेद 189, 193 194, 195 तथा 196 ;

अनुच्छेद 198 ; अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4) अनुच्छेद 200 201 और 201 ;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का सम्बंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सम्बन्धों और मतों से है,

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक ; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का सम्बंध शापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) संविधान में राज्य पाल के प्रति किसी निर्देश का अर्थ) उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधानमंडल या विधान सभा के प्रति किसी निर्देश का, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी शक्ति से है, अर्थ जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निर्देश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निर्देश लगाया जाएगा) ;

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) अनुच्छेद 259 तक और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगा और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड (1) के अधीन उस सीमा तक जो जहां तक यह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(iv) संविधान में राज्य के विधान मण्डल के या एतद्द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निर्देश है, और पंजाब साधारण खण्ड अधिनियम, 1898 (1898 का पंजाब अधिनियम 1) जिस रूप में पंजाब राज्य में लागू है और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 के 10 में) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होना मानों यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो :

नई दिल्ली ;

व० वे० गिरि,

15 जून, 1971

राष्ट्रपति

नई दिल्ली ;

38/24/71—पोल-I (ए')

15 जून, 1971

गोविन्द नारायण, सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th June 1971

G.S.R. 945.—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued by me on this the 15th day of June, 1971 under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Punjab and all the powers vested in, or exercisable by, the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI ;

The 15th June, 1971.

V. Y. GIRI,

President.

NEW DELHI :

The 15th June, 1971.

GOVIND NARAIN,

Secretary.

आदेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1971

जी० एस० आर० 945 राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 1971 के जून के 15वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि पंजाब राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन यह उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल से

निहित या प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के अध्याधीन रखते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य होगी

नई दिल्ली,
15 जून, 1971

ब० ब० गिरि,
राष्ट्रपति

[सं० 38/24/71-पील-1 (ए)]

नई दिल्ली,
15 जून, 1971

गोविन्द नारायण सचिव ।

